



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126444

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 23405 वर्ष 2026

श्रीमती नीरज यादव और एक अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सचिन कुमार शर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 38

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता संख्या-1 अर्थात् श्रीमती नीरज यादव की जन्म तिथि 15.5.2001 है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र की प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। आधार कार्ड के अनुसार, जो रिट याचिका के साथ संलग्न है, याचिकाकर्ता संख्या-2 की जन्मतिथि 6.7.1997 है। रिट याचिका में कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता शादीशुदा हैं और उनकी शादी 10.2.2025 को मुरादाबाद के हरथवला में भगवान शिव मंदिर में संपन्न हुई है। आगे कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता शांति से रह रहे हैं लेकिन पूरी तरह से अवैध रूप से प्रतिपक्षी संख्या-4 परिवार के सदस्यों के साथ उन्हें परेशान कर रहे हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे वयस्क हैं और अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उक्त कारण से, प्रतिपक्षी संख्या-4 और परिवार के सदस्य नाराज हो गए हैं और याचिकाकर्ताओं के जीवन के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि उन्हें धमकी दी जा रही है और परेशान किया जा रहा है।

4. याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में कहा है कि वे पत्नी और पति के रूप में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिपक्षी अपने परिवार के सम्मान के लिए उन्हें खत्म कर सकता है। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

5. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, निजी प्रतिपक्षी को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. उच्चतम न्यायालय ने फैसलों की एक लंबी श्रृंखला में कानून का फैसला किया है कि जहां एक लड़का और एक लड़की बड़े हैं और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ रह रहे हैं, तो उनके माता-पिता सहित किसी को भी उनके साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। ज्ञान देवी बनाम ज्ञान देवी अधीक्षक, नारी निकेतन, दिल्ली और अन्य, (1976) 3 एस.सी.सी.234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2006) 5 एस.सी.सी.475; और, भगवान दास बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2011) 6 एस.सी.सी.396, जिसका उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के साथ-साथ दीपिका और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2013 (9)ए.डी.जे. 534 में लगातार पालन किया गया है। ज्ञान देवी (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

"7. ... याचिकाकर्ता की जन्मतिथि जो भी हो, तथ्य यह है कि वह वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु की है। चूंकि याचिकाकर्ता स्वयं अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विधिसम्मत रूप से सुई ज्यूरिस (सक्षम) है, इसलिए उस व्यक्ति की उसकी पसंद पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है जिसके साथ उसे रहना है, न ही उस स्थान के संबंध में कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां उसे रहना चाहिए। अदालत या याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भी ऐसे मामले में याचिकाकर्ता की राय या वरीयता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई गड़बड़ी होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ पुलिस अधीक्षक, संभल से संपर्क करेंगे। संबंधित प्राधिकारी/अधिकारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से आदेश की ऐसी कम्प्यूटरीकृत प्रति की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे और लिखित रूप में इस तरह के सत्यापन की घोषणा करेंगे, जो याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेगा।

8. निजी प्रतिपक्षी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि अभिलेखों पर लाए गए दस्तावेज मनगढ़ंत या जाली हैं, तो इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन दायर करना उसके लिए खुला होगा।

9. याचिकाकर्ता तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं।

10. यदि याचिकाकर्ता उपरोक्त निर्धारित अवधि के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण नहीं करा सके, तो इस आदेश के तहत दी गई सुरक्षा स्वचालित रूप से निरस्त हो जाएगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के कथित विवाह पर निर्णय नहीं दिया है और यह आदेश किसी भी तरह से उनकी शादी की वैधता के बारे में राय व्यक्त नहीं करता है।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

13. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पड़िया)

9 जून 2026

सुमैरा